



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—बाल्पर्च
PART I—Section I

प्राधिकार द्वारा प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 208]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 29, 1979/कार्तिका 7, 1901

No. 208] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 29, 1979/KARTIKA 7, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह भाग संकलन के क्रम में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भारिणज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारीता मंत्रालय
(भारिणज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना सं० ५३ भाई दी सी (पी एन) /७०
नई दिल्ली, २९ अक्टूबर, १९७९

भारात व्यापार नियंत्रण

विषय- भारत स्वीडन विकास सहयोग समझौता, १९७९ के अन्तर्गत जारी किए गए भारात साइर्सेस के लिए लागू होने वाले नियम लिया जाते हैं।

मित्रिल सं० आई० पी० सी० ३९/८/७८—भारत -स्वीडन विकास सहयोग समझौता, १९७९ के अन्तर्गत भारात साइर्सेस के नियंत्रण को नियंत्रित करने वाली जैसी शर्तें प्रस्तुत सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट में दी गई हैं, जो जानकारी के लिए अधिकृतिकी जाती हैं।

सी० बैंकटरेन, मुख्य नियंत्रक, भारात नियंत्रि।

भारिणज्य विभाग की सार्वजनिक सूचना सं० ५३ भाई दी० सी० (पी० एन) /७९ दिनांक २९-१०-७९ के लिए परिशिष्ट।

ग्राम्य

भारत—स्वीडन विकास समझौता, १९७९ के अन्तर्गत स्वीडन को सहयोग दो बांह से युक्त है—(१) सामान्य भारात और (२) स्वीडन से भारात। प्रथम बांह के मामले में प्रतियोगी विश्वव्यापी निविदा के प्रधार पर भारात विश्व में कहीं से भी किए जा सकते हैं परन्तु द्वितीय बांह के मामले में भारात केवल स्वीडन से किए जा सकते हैं प्रधार भारत का स्वीडन में विनियमित होना आवश्यक है।

भारात साइर्सेस

भारात साइर्सेस भारत-बीमा भाड़ा के भावार पर संविदा करने के लिए ४ महीने की और पोतलदान एवं मूर्गान पूर्ण करने के लिए १२ महीने की प्रारम्भिक वैधता प्रवधि के साथ जारी किए जाएंगे। सभी पोतलदान साइर्सेस की वैधता प्रवधि समाप्त होने से एक महीने के भीतर प्रवध्य पूर्ण करने चाहिए।

२. प्रत्येक भारात साइर्सेस पर एक शीर्षक “भारत-स्वीडन विकास सहयोग समझौता, १९७९ सामान्य भारात” भव्यता “भारत-स्वीडन विकास सहयोग समझौता, १९७९ स्वीडन से भारात” जैसा भी मामला हो, होगा। साइर्सेस कोड वर्गीकरण संख्या में प्रत्यय (“भार० एस० ब० ब० ब०”) होंगे। ये प्रत्यय भारात साइर्सेस भेजते समय मुख्य ज़िल्हांक, भारात-नियंत्रि के पहले में भी छोहराए जाएंगे।

३. भारात साइर्सेस की प्राप्ति के १५ दिनों के भीतर भारातको भारात साइर्सेस की संख्या, दिनांक और मूल्य तथा सम्बाद्य तिथि जिस तक संविदा दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे, निर्विष्ट करते हुए भारात-साइर्सेस की प्राप्ति के तत्व से आधिक कार्य विभाग (इन्स्प्र० आई० ए० अनुभाग) को सूचित करना चाहिए।

४. जब तक भीचे के पैरा २१ में यथा निर्दिष्ट ४ महीनों की निर्धारित प्रवधि के भीतर पूर्ण संविदा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे तब तक संविदा करने से सम्बन्धित शर्तों का पालन किया गया नहीं माना जाएगा।

5. यदि, इस शर्त का पालन 4 महीने के भीतर नहीं किया जाएगा तो आयात लाईमेंस अवैध हो गया समझा जाएगा।

6. लेकिन, पार्टी द्वारा समय के भीतर शर्त का पालन न करने के कारण देने हुए एक आवेदन पत्र देने पर आयात लाईमेंस पुनर्वैध किया जा सकता है। पुनर्वैधीकरण के लिए आवेदन पर लाईमेंस प्राधिकारी द्वारा गुणों के आधार पर विवार किया जाए और लाईमेंस संविदा के लिए अधिन ने अधिक शर्तें आरंभीनों की अवधि के लिए पुनर्वैध किया जाएगा। इस अधिन से आगे किसी प्रकार का पुनर्वैधीकरण करने के लिए आधिक कार्य विभाग (आई० ए० अनुभाग) के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता हीगी।

संविदा करना

7. एक संविदा में सामान्यतः दोनों पार्टियों अर्थात् भारतीय आयातक और विदेशी मंभरक द्वारा हस्ताक्षरित एक समझौता शामिल होगा अथवा इसमें भारतीय आयातक द्वारा दिया गया सम्बोध और विदेशी मंभरक द्वारा उस आदेश का स्पष्ट रूपमें में स्वीकृति पत्र हो सकता है। सम्बोध पार संभरकों के भारतीय अधिकताओं के लिए आदेश और/या ऐसे भारतीय अधिकताओं द्वारा आदेश का पुष्टिकरण स्वीकृत नहीं है।

8. दो पार्टियों के बीच विभिन्न शर्तों को बार-बार समीक्षित/परिशोधित करने से सम्बन्धित पत्र-पत्रवहार के अनुक्रम से समाविष्ट संविदा स्वीकृत नहीं की जाएगी। ऐसे भागों में, दोनों पार्टियों द्वारा स्वीकृत शर्तों सहित और हस्ताक्षरित दस्तावेज़ तैयार करना आवश्यक है।

9. सामान्यतः पक्की कीमतों के आधार पर लाईमेंस के पूरे मूल्य के लिए विदेशी संभरक के साथ एक से संविदा की जानी है। लेकिन, विशेष कारणों से यदि एक से अधिक संविदा करना अवश्यक हो जाता है तो उनके लिए कारण देने हुए आधिक कार्य विभाग को पूर्व अनुमति दें लेनी चाहिए।

संविदा की शर्तें

सामान्य

10. निजी क्षेत्र के आयातकों के लिए यह आवश्यक है कि वे सागत-भीमा भारें या सागत और भारें के आधार पर संविदा करें। उन्हें चाहिए कि वे जहाज पर्यंत नियुक्त मूल्य यीमा प्रभार एवं भारें को अलग-अलग स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करें।

संविदा सरकारी अधिकरण या सार्वजनिक क्षेत्र सम्यात द्वारा केवल लागत और भाड़ा के आधार पर ही होनी चाहिए।

यदि कोई आयातक जहाज पर्यंत नियुक्त मूल्य के आधार पर कोई संविदा करने का इच्छुक है, तो पार्टी को ऐसा करने के लिए कारण देने हुए आधिक कार्य विभाग (आई० ए० अनुभाग) यिन मंत्रालय, नई दिल्ली का पूर्व अनुमोदन मांगना चाहिए।

11. यदि विदेशी मंभरक के भारतीय एजेंट को कोई कमीशन युक्ताया जाना है, तो उसे संविदा के मूल्य से अलग दिखाया जाएगा। भारतीय एजेंट का कमीशन भारतीय रूपमें मूल्य के बुकाया जाएगा परन्तु आयात लाईसेंस के कुल मूल्य के प्रति संमिलित किया जाएगा।

12. संविदा का मूल्य उसी मुद्रा में अक्षत होना चाहिए जिसमें विदेशी संभरक को भुगतान किया जाना है। इन धन राशियों का रूपमें परिवर्तन सीमानुक अधिनियम, 1962 के खंड 15 के प्रस्तावित राजस्व विभाग (सीमा मूल्क) द्वारा अधिसूचित मुद्रा विनियम की वर पर और आयात लाईमेंस जारी होने की सारी बातों परिचलित मुद्रा विनियम की दरों पर किया जाएगा।

संविदाओं की मूल्य सीमाएँ

13. प्रत्येक संविदा का मूल्य 75 हजार रुपये के बराबर की घनराशि से कम नहीं होना चाहिए।

माल का उद्दाम स्थान

14. (1) प्रथम खण्ड अर्थात् आमदा में उल्लिखित राजान्य आयात खण्ड के मामले में, विदेशी भी देश से यिन प्रतिवन्ध के आयात किए जा सकते हैं और ये आयात जहाज तक साध्य हो अन्तर्राष्ट्रीय प्रसिद्धिगति के आधार पर होने चाहिए।

(2) आमदा में उल्लिखित द्वितीय खण्ड अर्थात् स्वीडन से आयात के अधीन माल स्वीडन में विनियमित होना चाहिए या वे जाने वाली सेवाएँ स्वीडन मूल की होनी चाहिए। माल के स्वीडन में विनियमित होने के नाम्यन्य में या स्वीडन मूल की सेवाओं के सम्बन्ध में एक अन्वन्ध समाविष्ट किया जाएगा।

(3) लाईसेंसधारी को नीचे के पैरा 21 (3) में उल्लिखित संविदा वस्तावेज प्रस्तुत करते समय प्रांत की गई बोनियों और विशेष सभरक मूल माल का चुनाव करने के लिए कारणों का एक विवरण-पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

पोतलदान

15. जहाज तक सम्भव हो, प्रत्येक ऐसे वितरण पोत लदान के महीने को मकानित करते हुए संविदा में वितरण/पोत परिवहन सम्बन्धी भन्नसूचिया विशिष्ट शर्तों में होनी चाहिए।

पोतलदान भी शर्ते

16. स्वीडन कोडिट में विलम्बित भुगतानों की व्यवस्था नहीं है। इसलिए, विदेशी संभरकों को पोतलदानों के लिए नकद में पूर्ण भुगतान निम्नलिखित कार्डिकार्डों में व्यापनिर्विष्ट किए जाएंगे।

अधिक भुगतान

17. संभरकों के जहाज पर्यंत नियुक्त मूल्य के अधिक से अधिक 10 प्रतिशत तक अधिक भुगतान संविदा लागू होने के समय प्रदान किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की चुक होने पर वित्त मंत्रालय, अधिक कार्य विभाग (आई० ए० अनुभाग) का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए।

अन्य भुगतान

18. उपयुक्त भुगतानों के बाद योग घनराशि प्रत्येक पोतलदान के माल के मूल्य के भन्नसार पोत परिवहन भन्नसूची के आधार पर तथा अनुपात में देय होगे।

19. यह विशेष रूप से मुनिविचत कर लेना चाहिए कि भुगतान की शर्तों अर्थात् संविदा प्रभावी होने पर येय घनराशि और यह कि पोतलदानों आदि के लिए देय घनराशि संविदा में प्रति शर्तों में विस्तार के साथ विवरणों/भुगतानों आदि की प्रभावसूचियों प्रदर्शित करें; एवं निर्दिष्ट की गई है। प्रधानगत गारम्सी

20. समझौते में जो प्रधानगत गारम्सी(यां) आयातक के हित की सुरक्षा के लिए आवश्यक हों उनके लिए वह प्रबन्ध और व्यवस्था कर सकता है।

प्रस्तुत किए जाने वाले अपेक्षित संविदा प्रलेखों के व्यौदे

21. संविदा में यह किए जाने के 20 दिनों के भीतर सी आयातक को निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ एक पत्र वित्त मंत्रालय, अधिक कार्य विभाग (आई० ए० अनुभाग) सार्व लकाक, नई दिल्ली को भेजना चाहिए:

(1) अप्रेजी भाषा में विधिवत निर्धारित और भारतीय आयातक तथा विदेशी संभरक दोनों द्वारा हस्ताक्षरित संविदा को और आगे होने वाले किसी प्रकार के संशोधन की बात प्रमाणित प्रतियाँ।

(2) संविदा के निष्पातन/आयातक द्वारा दिए गए भ्रात्याकार को विवेशी संभरक की, की गई स्वीकृति तिथि को संविदा करने के लिए वैष्ण आयात लाइसेंस मुद्रा (विनियम नियन्त्रण) की ही फोटोस्टेट प्रतियाँ।

(3) सामान्य आयात खण्ड के मामले में उपर्युक्त परा 14 (3) में वर्णित बानियों का विवरण-पत्र।

(4) ही प्रतियों में भ्रात्याकार-पत्र म्होरे।

संविदा पर आगे कार्रवाई केवल तभी की जाएगी जबकि आयातक द्वारा वे सभी वस्तविक प्रत्युत कर दिए गए हों।

प्राधिकार-पत्र

22. यदि संविदा पूर्ण है, दस्तावेज प्राप्ति मही है, आयात लाइसेंस संविदा करने के लिये वैष्ण है और भारत स्वीकृत विकास सहयोग समझौता 1979 के अन्तर्गत वित्तव्यापार के लिए उपर्युक्त समझा जाना है तो वित्त मंत्रालय अनुबन्ध-2 जैसा एक प्राधिकार-पत्र जारी करेगा।

भुगतानों के तरीके

23. (1) विवेशी संभरकों को मुगतानों को व्यवस्था माला पत्र स्थापित करने के तानान्त्र वैष्ण सूची के माध्यम के अधीन पर की जायेगी।

(2) भारतीय आयातक केवल तब साक्षपत्र स्थापित करेगा जब कि पिछले पैरा में उल्लिखित प्राधिकार-पत्र वित्त मंत्रालय द्वारा जारी कर दिया गया हो और यह साक्ष-पत्र सर्वथा ऐसे प्राधिकार पत्र को व्यवस्थाओं के अनुसार होगा।

(3) विवेशी मुद्रा विनियम का प्राधिकृत व्यापारी भारतीय बैंकर किसी भारतीय आयातक को मालान्त्र स्थापित करने के लिए तब तक सुविधाएं प्रदान नहीं करेगा जब तक उसे इन सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय से एक प्राधिकार-पत्र सीधे ही प्राप्त न हो गया हो और भारतीय बैंकर केवल ऐसे प्राधिकार पत्र में निहित अनुदेशों के अनुसार ही ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा या धन परेषणों की अनुमति देगा।

24. उम विवेशी बैंक का जिसके साथ साक्षपत्र स्थापित किया गया है यह उनरदायित्व होगा कि वह अपरकाम्य बीजकों/पोत परिवहन वस्ता बेंजों का एक सेट सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय यूसीओ बैंक विलिंग, पालियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को ठोक उसी समय भेजेगा जिस समय वह ऐसे दस्तावेज उस भारतीय बैंकर को भेजता है जिसने साक्षपत्र छोला है। भारतीय बैंकर के लिए इस सम्बन्ध में उसके द्वारा स्थापित किए जाने वाले साक्ष-पत्र में एक शर्त शामिल करना आवश्यक है। तथ्य यह है कि इस प्रकार अपरकाम्य पोत परिवहन वस्तावेजों के भेजे गए सेट को विवेशी बैंक द्वारा भारतीय बैंकर को भेजे गए व्यायामानक पत्र में लिखा जाएगा, बाद छाला (भारतीय बैंकर) दस्तावेजों पर आगे कार्रवाई करने से पहले इस बात की विशेष रूप से जांच करेगा।

25. (1) मुगतानों की व्यवस्था करने समय भारतीय आयातक फार्म* "ए" की एक अनिवार्य प्रति भरेगा जो उसके बैंक द्वारा मुगतान होते ही आयातक को सूचना देने के लिए नहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक वित्त मंत्रालय यूसीओ बैंक विलिंग, नई दिल्ली की भेजी जायेगी। वह यह भर जिसके साथ प्रपत्र "ए-1" साथ ही साथ प्रपत्र "ए-1" भेजे जाएंगे उसमें उम केंटिंग एवं सेप्टेंट का संकेत होता चाहिए जिसके प्रत्यार्थ आयात लाइसेंस जारी किया गया था।

(2) भारतीय आयातक और भारतीय बैंकर दानों यह सुनिश्चित करेंगे कि अपेक्षित सूचना सही, पूरी और विशिष्ट शब्दों में संबंधित कालान्तरों के मामले दी गई है।

*स्लिव बैंक द्वारा इंडिया द्वारा धन परेषणों के लिए निर्धारित आवेदन पत्र का प्रपत्र।

(3) आगे फार्म "ए-1" पर भारतीय बैंकर के प्राधिकृत प्राधिकारी के हस्ताक्षर भी इसके कार्यालय को मोहर के साथ होते।

टिप्पणी—इन अवस्थाओं में यह सुनिश्चित करना लाइसेंसदारों का अपना उत्तरदायित्व समिन्हित नहीं है कि सभी फार्म "ए-1" उसके बैंक द्वारा वित्त मंत्रालय को दुर्लिख भेजे गए हैं।

धन बापती:

26. यदि विवेशी संभरक या बीमाकर्ता से भारतीय आयातकों द्वारा कोई धन बापती प्राप्त की जाता है तो सम्बन्धित ब्यौरों के साथ प्राप्त की गई धनराशियों को प्रत्यक्षित करने हुए एक पूर्ण रिपोर्ट अनुबन्ध-3 में दिए गए प्रपत्र में सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियन्त्रक, वित्त मंत्रालय को भेजी जायेगी।

भारतीय आयातकों द्वारा वास्तविक भुगतानों की रिपोर्ट भेजना

27. जब और जैसे ही भारतीय आयातकों द्वारा समुदायार सभरकों को अनग-अनग संविदाओं के भत्ते वास्तविक भुगतान कर दिए जाते हैं तो उसे नियमावधि रूप से इसकी रिपोर्ट सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियन्त्रक, वित्त मंत्रालय, भारतीय कार्य विभाग यूसीओ बैंक विलिंग, पालियामेंट स्ट्रीट, स्ट्रीट, नई दिल्ली को भेजनी चाहिए। भुगतानों की रिपोर्ट भेजते समय आयातकों को आहिए कि वे भेज दी गई/भेजी जा रही प्रत्येक संविदा के मध्य आयातित उपकरण के उद्देश्यों का संकेत भी करें ये रिपोर्ट वास्तविक भुगतान हो जाने के एक सम्भाल के भीतर ही महायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियन्त्रक, वित्त मंत्रालय, भारतीय कार्य विभाग, यूसीओ बैंक विलिंग, पालियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को भेज दी जानी चाहिए।

विविध

28. लाइसेंस के अधीन आयात किए गए माल का उपयोग उचित उद्योगीलता और क्षमता के साथ होना चाहिए। लाइसेंस के अधीन आयात किए गए माल का प्राप्ति की तिथि से कम से कम चार वर्षों की प्रयोग्यि के लिए आयात: (1) ऐसे माल की पहचान के लिए आवश्यक और उसके उपयोग का सभी सम्बन्धित रिकार्ड रखेगा, (2) केंटिंग की रकम के बच्चों से सम्बन्धित और ऐसे रकमों से प्राप्त माल और सेवाओं से सम्बन्धित ऐसी सूचना भारत सरकार को प्रस्तुत करेगा या प्रस्तुत करने का कारण उत्पन्न करेगा जो भारत सरकार द्वारा मांगा जाए और (3) भारत सरकार के प्रतिनिधियों और स्वीडन के अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण की ऐसे माल और सेवाओं के उपयोग का प्रज्ययन करयेगा यदि वे ऐसा करने का अनुरोध करें।

29. भारतीय आयातक और विवेशी संभरकों के बीच यदि कोई विवाद उड़ेगा तो भारत सरकार उसके लिए कोई उत्तरदायित्व नहीं सेगी।

30. भारतीय आयातकों को आयात लाइसेंस से सम्बन्धित किसी एक मामले या सभी मामलों के सम्बन्ध में और स्वीडन के प्राधिकारियों के साथ केविट समझौते के अन्तर्गत सभी वायित्वों को पूर्ण करने के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निवेशों, अनुदेशों या आवेदनों का तुरन्त पालन करना होगा।

31. इसमें निर्धारित किसी शर्त के किसी प्रकार उल्लंघन या भंग करने पर आयातक और नियंत्रण (नियंत्रण) प्रधिनियम, 1947 के और उसके प्रनीत जारी किए गए प्रावेदनों के प्रधीन समूचित कार्यवाई की आपूर्ति।

अनुवाद-1
(दो प्रतियों में)
[कविका-21 (4)]

देवा मे,
सचिव,
वित्त मंशालय, आधिक कार्य विभाग,
मार्ह० ऐ० अनुवाग, नार्य ब्लाक,
नृ दिल्ली-१

विषय - भारत स्वीडन विकास सहयोग समिक्षा, 1979 इसके प्रत्य-
र्गत आधार ।

महोदय,
उपर्युक्त समझौते के घट्टर्गत के प्रायात
(माल तथा सेवाओं का संश्लिष्ट विवरण)
— — — — —

(क) संस्कृत न है लिखावत यार नहीं ४ —

(क) आयात का नाम तथा पता
 (ख) प्रायात लाइसेंस
 (१) सख्ता
 (२) दिनांक
 (३) अनराशि
 (४) कब तक वैध है —

(क) सविदा के लिए
 (ख) पौत्रस्वाम के लिए

(ग) विदेशी समरक का नाम तथा पता
 (घ) सविदा का दिनांक
 प्रधाना
 प्रावेश के लिए समरक के प्रतितम अनुबोधन पत्र का दिनांक
 (ङ) प्राप्तात किए जाने वाले माल का संक्षिप्त विवरण
 (च) सविदा का मस्त्र

जहाज पर नि प्राप्त मूल्य विवेशी मुद्रा में समतुल्य भारतीय रुपए में

माता
मीमा

जोड़

(४) सविदा में यथा निर्धारित विनाक समरण की अनुशूलियों के प्राधार पर विभिन्न तिथियाँ जिनको उपकरण सदान किये जायेंगे अथवा सेवा निष्पादित की जाएंगी, प्रत्येक सदान अथवा निष्पादित सेवाओं का मर्य

(ज) वह तिथि जिसकी सविदा
के प्रस्तर्गत भुगतान करने
होगे —

(1) प्रथम भुगतान के दिनांक विवेशी मुद्रा में राखि
सम्बन्ध में

(2) अर्थ भुगतानों के सम्बन्ध में

(म) विवेकी मुहा विनियम में
प्राधिकृत उस व्यापारी/
बैंक का नाम और पता
जिसके माध्यम से मालपत्र
खोलने के लिए व्यक्तस्थाएं
की जाएंगी ।

(म) उस विदेशी बकर का नाम और पूरा पता जिसके पास साथपक्ष स्थापित किया जाएगा ।

2 सविया की 4 प्रतिया अथवा प्रत्येक ग्रामीण तथा स्वीकृति पत्र तथा सशोधन (यदि कोई हो) की चार प्रमाणित प्रतियां तथा आयात साइंसेंस की दो फोटोस्टेट प्रतियां सलग्न की जाती हैं।

3. विदेशी संभरक का चुनाव प्रत्यारूपीय जांच-पहताल के आधार पर किया गया है और श्रावण का एक विवरण मलग्न है। माल स्वीडन मूल के हैं और विदेशी संभरक का माल के मूल का प्रमाण-पत्र सलग्न है।

4 आप से भनुरोध किया जाता है कि भारत स्वीडन विकास सहयोग समझौता, 1979 के प्रन्तरीत वित्त दान के लिए सविदा भनुमोदित करा लें और उपर्युक्त मकेतिक उनके बैंकर के माध्यम से मधरखो की भुगतान के लिए प्राधिकार पद्ध जारी करें।

मवदीय,
लाइसेंसधारी

प्रमुखन्ध- 2

सख्ता एक
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आधिक कार्य विभाग
नई दिल्ली वित्त

सेषा अ-

(भारतीय वैकर)

विषय — भारत-स्वीडन विकास सहयोग समझौता, 1979 के अन्तर्गत की गई विविध समान्य प्रायान्त्र/स्वीडन प्रायात्र सेमेट्रिय महोदय.

सर्वेश्वी ने भ/रत-स्वीडन विकास
 [भारतीय भाषायातक]
 सह योग समझौता, 1979 के अन्तर्गत आरी किए गए लाइसेंस सख्त्या . . .
 दिनांक मूल्य . . . के मद्दते . . .
 रुपए की धनराशि लागत बोमा-भाजा/लागत तथा भाजा के लिए . . .
 का सभरण करते के लिए सर्वेश्वी . . . के साथ संविदा
 कर ली है। सविया की एक प्रति सुलग्न की जरूरती है।

2. की धनराशि में से की धनराशि
भारतीय मुद्रा में भारतीय अभिकर्ता के कमीशन के रूप में चुकाई जानी
है इसलिए विदेशी मुद्रा में समरक को नुकाई जाने वाली धनराशि जो
कि स्थीड्डन ऐडिट में से वित्तयुक्त की जायेगी वह . . .
की धनराशि होगी ।

3. आपको सहायता लेखा और लेखा परीक्षा नियत्कर, यू० मी० धो० बैंक विलिंग, 10 पालियामेट स्ट्रीट, नई दिल्ली को सूचना देते हुए इस पत्र के जारी होने की तारीख से 30 दिनों की प्रबंधि के भीतर

(चिकित्सा सम्बन्धी)
के नाम में उनके बैंकर अध्यात्म संवर्धी के माध्यम
से एक साख्यपत्र खोलने के लिए प्राप्तिकृत किया जाता है।

4. सार्वजनिक खोलों से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि भारतीय आयातक के पास वैध आयात लाइसेंस है ।

5. मुद्रा विनियोग नियंत्रण नियम पुस्तक के अध्याय 13-ख-8 के अनुसार आपके लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि सार्वजनिक समाज होलों की तिथि और संख्या आयात लाइसेंस में यथा अधिकृत पोतलदान के लिए अन्तिम तिथि के बाद 45 दिनों से अधिक की नहीं है ।

6. सार्वजनिक में यह भी व्यक्तिया होगी कि सर्वेशी (विदेशी बैंक)

प्राप्तकाम्य पोतलदान दस्तावेजों के एक सेट की इस संबंध में सीधे ही सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, यू० सी० ओ० बैंक विलिंग, पालियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को भेजेगा कि प्रत्येक भुगतान पूरा कर लिया गया है ।

7. आप से अनुरोध है कि भुगतान के तुरन्त बाद ही भारत स्वीडन विकास सहयोग समझौता दिनांक 1-6-79 के अन्तर्गत आयात करने के लिए लाइसेंस गर्तों की कंडिका 2.5 के अनुसार विदेशी संभरक को प्रेषित धनराशि का विवरण दर्शाते हुए "प्रपत्र ए १" की अतिरिक्त प्रति भहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, आधिकारी कार्य विभाग, यू०सी०ओ० बैंक विलिंग, पालियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को भेजें ।

8. कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दें ।

भवदीय,

अवर सचिव, भारत सरकार

1. संविदा की एक प्रति के साथ प्रतिलिपि रिजर्व बैंक आफ इंडिया, मुद्रा विनियोग नियंत्रण विभाग को प्रेषित

2. बिना अनुमति के प्रति निम्नलिखित को प्रेषित:—

1. (भारतीय आयातक)
2. (विदेशी संभरक)
3. (विदेशी बैंक)

यह निर्वेदन किया जाता है कि प्रत्येक भुगतान पर भुगतान परामर्श के साथ पोतलदान तथा अन्य दस्तावेजों (अपरकाम्य) का एक सेट सीधे ही सहायता लेखा एवं परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, यू०सी०ओ० बैंक विलिंग, पालियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली (भारत) को भेजा जाए ।

3. संविदा तथा आयात लाइसेंस की एक प्रति के साथ सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक को ।

4. रिजर्व बैंक आफ इंडिया, मुद्रा विनियोग विभाग, बम्बई ।

अवर सचिव, भारत सरकार

अनुरोध 3

(कंडिका 26)

आयातों के मम्बल्य में अस्त्य अवतरण, सति आदि के लिए दार्तों के निपटान के मध्ये विदेशी संभरकों/पोतलदानिकों/बीमा कंस्ट्राइंस से प्राप्त धन वापसीयों के द्वारा को वर्णन वाली रिपोर्ट

1. भारतीय आयातक का नाम
2. आयात लाइसेंस की संख्या तथा दिनांक
3. आयात लाइसेंस का मूल्य
4. प्राधिकार-पत्र की संख्या तथा दिनांक
5. प्राप्त की गई धन वापसी की राशि
6. उसकी किसी भी धन वापसी (मंकिल व्यूहा वें)

7. उस सम्बद्ध प्रपत्र "ए" के लिए संदर्भ जिसके अन्तर्गत विदेशी संभरकों को प्रारिम्बिक भुगतान किया गया था । (विदेशी मंत्रालय को प्रपत्र "ए" भेजते समय भारतीय बैंक का नाम तथा उनके पत्र की संख्या तथा दिनांक का संकेत करें) ।

8. क्या प्राप्त धन वामियों का प्रयोग माल की बदलाई के लिए किया जाता है या नहीं ? यदि नहीं तो इन बात का सुनिश्चित कर लें कि विदेशी मुद्रा विनियोग के भीतरी प्रेषण द्वारा वास्तव में धनराशि प्राप्त कर ली गई है और इसे रुपए में भुना लिया गया है ।

9. अन्य कोई आवश्यक ज्ञाते ।

आयात करने वाली फर्म के प्राधिकारी के हस्ताक्षर सेवा में,

महापता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, विस मंत्रालय आधिकारी कार्य विभाग यू०सी०ओ० बैंक विलिंग, 10 पालियामेंट स्ट्रीट नई दिल्ली-१

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION

(Department of Commerce)

PUBLIC NOTICE NO. 53-ITC(PN)/79

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 29th October, 1979

Subject.—Terms and Conditions applicable to import licences issued under the Indo-Swedish Development Co-operation Agreement, 1979.

File No. IPC/39/8/76.—The terms and conditions governing issuance of import licences under Indo-Swedish Development Co-operation Agreement, 1979, as given in Appendix to this Public Notice are notified for information.

C. VENKATARAMAN,

Chief Controller of Imports & Exports

APPENDIX TO DEPARTMENT OF COMMERCE PUBLIC NOTICE NO. 53-ITC(PN)/79 DATED 29-10-1979

PREAMBLE

Swedish Assistance under the Indo-Swedish Development Co-operation Agreement, 1979, consists of two segments (i) general imports and (ii) imports from Sweden. In the case of first segment, imports can be effected from any, where in the world on the basis of competitive global tendering but in the case of the second segment, the imports can be effected or services can be obtained only from Sweden, i.e., the goods must be manufactured in Sweden.

IMPORT LICENCE

1. The import licence will be issued on CIF basis, with an initial validity period of four months for contracting and twelve months for completion of shipments as well as payments. All shipments must be completed within a month from the expiry of the licence.

2. Each import licence will bear a superscription, "Indo-Swedish Development Co-operation Agreement, 1979 General Imports" for "Indo-Swedish Development Co-operation Agreement, 1979—Imports from Sweden" as the case may be. The suffixes in the licence code classification number will be "R/EW". These will also be repeated in the letter from the Chief Controller of Imports & Exports forwarding the import licence.

3. Within a fortnight of the receipt of the import licence, the importer should intimate to the Department of Economic Affairs (IA Section) the fact of receipt of the import licence indicating the number, date and value of the import licence and likely date by which the contract documents would be furnished.

4. The condition regarding contracting shall not be deemed to have been complied with unless complete contract documents, as provided in para 21 below, are furnished within the stipulated period of four months.

5. Where this stipulation is not complied with within four months, the import licence will be deemed to have become invalid.

6. The import licence may, however, be revalidated on an application by the party, wherein the reasons for not complying with the requirement in time should be stated. The request for revalidation would be considered by the licensing authority on merits and the licence will be revalidated for contracting for a further period not exceeding two months. Any revalidation beyond this period will require the prior approval of the Department of Economic Affairs (IA Section).

CONTRACTING

7. A contract will normally comprise an Agreement signed by both the parties viz. the Indian importer and the foreign supplier or it may comprise the order placed by the Indian importer and the letter of acceptance thereof in unequivocal terms by the foreign supplier. Orders on Indian Agents of the Overseas Suppliers and/or order confirmation by such Indian Agents are not acceptable.

8. A contract comprising a series of correspondence between the two parties frequently amending/revising the various provisions will not be generally accepted. In such case, it is necessary to prepare a final document including therein the terms agreed to and signed as such by both the parties.

9. Normally, one contract, on the basis of firm prices, has to be entered into with the foreign supplier for the whole amount of the licence. However, if for special reasons, conclusion of more than one contract becomes necessary, prior permission of the Department of Economic Affairs should be obtained, giving reasons for doing so.

TERMS OF CONTRACT

General

10. The importers in the private Sector are required to place the contracts on C.I.F. or C&F basis. They should clearly indicate F.O.B. price, insurance charges and freight separately.

Contract must be entered only on C&F basis, by a Government agency or a public sector undertaking.

If any importer desires to enter into a contract on f.o.b. basis, the party should seek prior permission of the Department of Economic Affairs, (IA Section), Ministry of Finance, New Delhi giving reasons for doing so.

11. If any commission is to be paid to the Indian agent of the foreign supplier, it will be shown separately from the value of the contract. The Indian agent's commission will be paid in Indian rupees but will be set off against the total value of the import licence.

12. The value of the contract should be expressed in the currency in which the payment is to be made to the foreign supplier. The conversion of these amounts into Rupees shall be made at the rates of exchange notified by the Department of Revenue (Customs) under Section 15 of the Custom Act, 1962 and prevailing on the date of issue of the import licence.

Value Limits of Contracts

13. The value of each contract should not be less than for an amount equivalent to Rupees seventy-five thousand (Rs. 75,000).

Origin of Goods

14. (i) In the case of the first segment, i.e., general imports segment, referred to in the preamble, imports can be made from any country without restriction and should, as far as practicable, be on the international competitive basis.

(ii) Under the Second segment, i.e. imports from Sweden, referred to in the preamble, the goods should be manufactured in Sweden or the services to be rendered should be of Swedish origin. A stipulation as to the Swedish manufacturing of goods or Swedish origin of services shall be incorporated in the contract.

(iii) The licensee should while submitting the contract documents referred to in part 21(iii), below, furnish a statement of the bids received and the reasons for selecting the particular supplier and goods.

Shipments

15. The contract should spell out delivery/shipping schedules in specific terms indicating the month of each such delivery/shipments, as closely as possible.

Any subsequent deviation from the shipping schedule should be promptly notified to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, IA Section, North Block New Delhi.

Payment Terms

16. The Swedish assistance does not provide for deferred payments. Full payment will, therefore, be, made to the foreign supplier in cash against shipments as indicated in the following paragraphs.

17. Advance Payments.—An advance payment upto a maximum of 10 per cent of the FOB price of the supplies can be provided at the time of the contract coming into force. In the case of any deviation in this regard, prior approval of the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (IA Section) should be obtained.

18. Other payments.—The amount left after the above payment will be payable pro rata according to the value of goods covered by each shipment, on the basis of the shipping schedule.

19. It should specifically be ensured that the terms of payment, e.g. amount payable on the contract becoming effective, and that payable against shipments etc. are set out in precise terms in the contract with details showing the schedule of deliveries/payments etc.

Customary Guarantee

20. The importer may arrange and provide for in the agreement customary guarantee(s) which may be necessary for safeguarding his interest.

DETAILS OF CONTRACT DOCUMENTS REQUIRED TO BE SUBMITTED

21. Within 20 days of the conclusion of the contract, the importer should send a letter accompanied by the following documents to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (IA Section), North Block, New Delhi :—

(i) Four certified copies of the contract and any further amendment(s) duly executed in English language and signed by both the Indian importer and the foreign supplier.

(ii) Two photostat copies of the import licence (Exchange Control copy) valid for contracting on the date of execution of the contract/acceptance by foreign supplier of the order placed by the importer.

(iii) Statement of bids mentioned in para 14(iii) above.

(iv) Other particulars stipulated in Annexure I, in duplicate.

The contract will be processed only after all these documents have been furnished by the importer.

LETTER OF AUTHORITY

22. If the contract is complete, the documents etc. are in order, the import licence is valid for contracting and is considered eligible for financing under the Indo-Swedish Development Co-operation Agreement, 1979, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs will issue a letter of authority as in Annexure II.

Method of Payments

23. (i) Payment to the foreign suppliers are arranged through normal channels by establishing a letter of credit.

(ii) The Indian importer will establish a letter of credit only after the letter of authority referred to in the preceding paragraph has been issued by the Ministry of Finance; the letter of credit will strictly be in accordance with provisions of the letter of authority.

(iii) The authorised dealers in foreign exchange (Indian bankers) will not provide facilities for establishing a letter of credit to any Indian importer unless a letter of authority in this regard has been received by them direct from the Ministry of Finance and Indian banker will provide such facilities or allow remittances only in accordance with the instructions contained in such a letter of authority.

24. It will be the responsibility of the foreign banker with whom the letter of credit has been established, to forward to the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi, one set of non-negotiable invoices/shipping documents at the same time as the foreign banker forwards such sets of documents to the Indian Banker which opened the letter of credit. It is necessary for the Indian Bankers to include a provision to this effect in the letter of credit to be established by them. The fact, that one set of non-negotiable shipping documents has been so forwarded will be noted down by the foreign bankers in the covering letter to the Indian Banker. The latter (Indian Banker) will check this point in particular before taking further action on the documents.

25. (i) The Indian importer will, at the time of arranging payments, fill in an additional copy of Form A1*, for being set by their Indian Banker direct to the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi, under advice to the importer as soon as the payment is made. The letter forwarding Form 'A1' as well as Form 'A1' shall indicate the credit and segment under which the import licence was issued.

(ii) Both the Indian importer and Indian banker will ensure that all the requisite information is given correctly, fully and in specific terms against the relevant columns.

(iii) Form 'A1' will further bear the signature of the authorised officer of the Indian Banker and stamped with its official seal.

Note : These arrangements do not absolve the licensee of his responsibility to ensure that all forms 'A1' are despatched promptly by his bank to the Ministry of Finance.

Refunds

26. If any refunds are received by the Indian importers from the foreign supplier or the insurer, a full report showing the amounts received, together with relevant particulars should be sent to the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance in the form given in Annexure-III.

Reporting of Actual Payments, etc. by the Indian Importers

27. The Indian importers should invariably report to the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi as and when actual payments against individual contracts are made by them to the overseas suppliers. While reporting the payments, the importer should also indicate briefly the purposes to which the equipment imported against each contract has been/is being put to. These reports should be sent to the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi within one week of the actual payments having been made.

MISCELLANEOUS

28. The goods imported under the licence should be used with due diligence and efficiency. For a minimum period of four years from the date of delivery of the goods imported under the licence, the importer shall (i) maintain all the relevant records necessary to identify such goods and their use, (ii) furnish or cause to be furnished to the Government of India such information as may be requested, concerning the expenditure of the proceeds of the Credit and the goods and services acquired out of such proceeds, and (iii) enable representatives of the Government of India and the Swedish International Development Authority to study the use of such goods and services if they so request.

*Application form prescribed by the Reserve Bank of India for remittances.

29. The Government of India will not undertake any responsibility for disputes, if any, which may arise between the Indian importer and the foreign supplier.

30. The Indian importer shall promptly comply with any directions, instructions or orders issued by the Government from time to time regarding any and all matters arising from or pertaining to the import licence and for meeting all obligations under the credit agreement with the Swedish Authorities.

31. Any break or violation of any of the condition prescribed herein will result in appropriate action under the Imports and Export (Control) Act, 1947, and others issued thereunder.

ANNEXURE-I

(In duplicate)

[Para 21 (iv)]

To

The Secretary,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
IA Section, North Block,
New Delhi-1.

Subject :—Indo-Swedish Development Cooperation
Agreement, 1979—Import under

Sir,

In connection with the import of

(short

description of the goods and services)
under the above Agreement, we furnish the following particulars:—

(a) Name and Address of Importer

(b) Import Licence :

(i) Number

(ii) Date

(iii) Amount

(iv) Valid upto

(a) for contracting
(b) for shipment

(c) Name and Address of the foreign supplier

(d) Date of the contract;

Or

Date of Supplier's final letter of acceptance of the order.

(e) Short description of the goods to be imported;

In foreign currency	In equivalent Indian Rupees
---------------------	-----------------------------

(f) Value of the contract :

FOB Price :

Freight :

Insurance :

Total :

Date	Value of shipment in foreign currency
------	---------------------------------------

(g) The different dates on which the equipment will be shipped, or services performed, the value of each shipment, or service performed, based on the delivery schedules as stipulated in the contract.

(h) The date on which payments under the contract will fall due
 (i) in respect of advance payment
 (ii) other payments.
 (i) Name and full address of the dealer/bank authorised in foreign exchange through whom arrangements for opening a letter of credit will be made :
 (j) Name and full address of the foreign banker with whom the letter of credit will be established.

2. Four certified copies of the contract or four copies each of the order and the letter of acceptance and of the amendment (if any), and two photostat copies of the import licence are enclosed.

3. The selection of the foreign supplier has been made on the basis of international enquiry and a statement of the orders received is enclosed/The goods are of Swedish origin and a certificate of the origin of goods from the foreign supplier is attached.

4. You are requested to get the contract approved for financing under the Indo-Swedish Development Cooperation Agreement, 1979, and issue authorization for payments to the suppliers through their bankers, mentioned above.

Yours faithfully,
 (Licencee)

ANNEXURE II
 (Para 22)
 No. F.
 Government of India
MINISTRY OF FINANCE
 (Department of Economic Affairs)
 New Delhi, the
 Letter of Authority No. G.I./S.I.

To
 (Indian Banker)
 Subject:—Contract entered under Indo-Swedish Development Cooperation Agreement, 1979—General Imports/Swedish Import Segment.

Dear Sirs,
 Messrs. _____ (Indian Importer)
 have entered into a contract with Messrs. _____ (foreign supplier)
 _____ for the supply of _____ for the amount of _____ (CIF/C&F)
 under the Indo-Swedish Development Agreement, 1979 against Licence No. _____ dated _____ issued thereunder for the value of Rs. _____
 A copy of the contract is enclosed.

2. Out of the above amount of _____ an amount of _____ is to be paid as Indian Agent's commission in Indian currency. The sum to be paid to the supplier in foreign currency which will be financed out of the Swedish Credit will therefore amount to _____

3. You are authorised to open a letter of credit for _____ in favour of Messrs. _____ (foreign supplier)
 _____ through their bankers, viz. Messrs. _____ within a period of thirty days from (foreign banker)
 the date of this letter under intimation to the Controller of Aid Accounts & Audit, UCO Banking Building, Parliament Street, New Delhi.

4. Before opening the Letter of Credit, it may please be ensured that the Indian Importer is in possession of a valid import licence.

5. In terms of Chapter 13 B-8 of the Exchange Control Manual, you are required, to ensure that the date of the expiry of the Letter of Credit is not later than seventy five (75) days after the final date for shipment as stated in the relative import licence.

6. The letter of credit will also provide that Messrs. _____ will forward directly to the Controller (foreign banker)

of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Banking Building, Parliament Street, New Delhi, one set of non-negotiable shipping documents as each payment is made.

7. You are also requested to forward to the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi, additional copy of the Form 'A1' showing particulars of remittances made to the foreign supplier in terms of para 25 of the Licensing Condition for imports under Indo-Swedish Development Cooperation Agreement, dated 1 June 1979 as soon as the payments are made.

8. Receipt of this letter may please be acknowledged.

Yours faithfully,
 Under Secy. to the Govt. of India

1. Copy with a copy of the contract forwarded to Reserve Bank of India, Exchange Control Department _____,

2. Copy without enclosures forwarded to :—

(i) _____ (Indian Importer)

(ii) _____ (Foreign Supplier)

(iii) _____ (foreign bank)

It is requested that on each payment, one set of shipping and other documents (non-negotiable) along with payment advice may be forwarded direct to the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi (INDIA).

(iv) Controller of Aid Accounts & Audit with a copy of the Contract and that of the import licence.

(v) Reserve Bank of India, Exchange Control Department, Bombay.

Under Secy. to the Govt. of India

ANNEXURE-III

(para 26)

Report Showing Details of Refunds Received from Foreign Suppliers/Shippers/Insurers Towards Settlement of Claims for Short Landings, Damages, etc. in Respect of Imports :—

1. Name of the Indian Importer :
2. No. and date of import licence :
3. Value of the import licence :
4. No. and Date of Letter of Authority :
5. Amount of refund received :

6. Nature and refund :
(give brief details)
7. Reference to the relative Forms 'A' under which payment was made initially to foreign suppliers (indicate name of the Indian banker and reference to their letter No. and date, forwarding from 'A' to Ministry of Finance).
8. Whether or not refunds received are to be utilised for replacement of goods; If not, confirm that amount has been actually received by inward remittance of foreign exchange and encashed into rupees :
9. Any other necessary particulars.

Signature of the Authorised Officer of the Importing Firm

